



प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्रा,
संयुक्त सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ०प्र०, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से जी०एस०टी०एन० को देय Advance User Charges की प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी०एस०टी०/2025-26/01/राज्य कर दिनांक 01.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी०एस०टी०एन० से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु Advance User Charges की प्रथम किस्त के रूप में रु० 3813.00 लाख की धनराशि का भुगतान जी०एस०टी०एन० को किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-35/2026/1/1292523/2026/11-4099/70/2025 दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी०एस०टी०एन० से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रु० 5000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ के निर्वर्तन पर रक्षित किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जी०एस०टी०एन० को एडवांस यूजर चार्जेज (Advance User Charges) की प्रथम किस्त के रूप में रु० 3813.00 लाख की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु, शासन के उपर्युक्त पत्र दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी०एस०टी०एन० से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रक्षित धनराशि रु० 5000.00 लाख में से रु० 3813.00 लाख (रुपये अड़तीस करोड़ तेरह लाख मात्र) धनराशि की वित्तीय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

धर्मेन्द्र मिश्रा
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र मिश्रा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।